वित्त मंत्रालय

की

उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

(केन्द्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रयोजित ₹500 करोड़ से कम लागत वाली योजना हेतु)

OUTPUT OUTCOME MONITORING FRAMEWORK

(For Central Sector and Centrally Sponsored Schemes costing less than ₹500 crore)

OF

MINISTRY OF FINANCE

2024-2025

विषय सूची

क्रमांक संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	मांग संख्या 30 – आर्थिक कार्य विभाग	1
i.	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीईएफ) (सीएस)	1
2.	मांग संख्या 32-वित्तीय सेवाएं विभाग	2-12
i.	भारतीय निर्यात – आयात बैंक (एक्जिम) की शेयर पूंजी में अभिदान (सीएस)	2
ii.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के शेयर का अंशदान (सीएस)	3
iii.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान (सीएस)	4
iv.	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के प्रचार – प्रसार / जागरूकता हेतु	5
	निधीयन सहायता (सीएस)	
V.	प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) (सीएस)	6
vi.	स्टैन्ड-अप इंडिया गारंटी निधि स्थापित करने के लिए एनसीजीटीसी को सहायता के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय	7
	सहायता (सीएस)	
vii.	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को वित्तीय सहायता और एपीवाई (सीएस) के अंतर्गत	8
	प्रचार अभियान के लिए पीएफआरडीए को वित्तीय सहायता	
viii.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) (सीएस) को इक्किटी सहायता	9

क्रमांक संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
ix.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को सरकारी प्रतिभूति बॉण्ड (सीएस) के निर्णय के माध्यम से इक्रिटी सहायता	10
x.	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) को पूंजी सहायता (सीएस)	11
xi.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत दिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) को ऋण गारंटी निधि के लिए वित्तीय सहायता (सीएस)	12
3.	मांग संख्या 33 – लोक उद्यम विभाग	13-14
i.	नए केन्द्रों का परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन स्थापना/नोडल एजेंसियों आदि को जोड़ना।	13
ii.	सीपीएसईज़ से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान विकास और परामर्श।	14

आर्थिक कार्य विभाग

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)			आउटपुट 2024-25			परिष	गाम 2024-25	
2024-25	आउटपुट	आउटपुट क्र.सं. संकेतक लक्ष्य 2024-25				क्र.सं.	संकेतक	लक्ष्य 2024-25
		1.1	आईआईपीडीएफ के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त नई परियोजनाओं की संख्या	15				
		1.2	निधियन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या।	12				
	आईआईपीडीएफ के अंतर्गत	1.3	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, जिनमें टीए (लेन-देन सलाहकार) नियुक्त किया गया है।	12	पीपीपी मॉडल पर बिड आउट		परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए	
25	सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की	1.4	टीए द्वारा नियुक्त परियोजनाओं की संख्या, जिनमें आरंभिक रिपोर्ट प्राप्त हुई।	10	िबिड आउट परियोजनाओं की संख्या।	2.1	बोलियां आमंत्रित की	6
	संख्या	1.5	टीए द्वारा नियुक्त परियोजनाओं की संख्या, जिनमें व्यवहार्यता अध्ययन प्राप्त हुआ।	8			गई हैं।	
		1.6	टीए द्वारा तैयार डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और बोली दस्तावेज वाली परियोजनाओं की संख्या।	6				
		1.7	आबंटित आईआईपीडीएफ बजट का उपयोग।	100%				

वित्त मंत्रालय मांग सं. 32

वित्तीय सेवाएं विभाग प्रतिफल परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क वित्तीय वर्ष 2024-25

1. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम) की शेयर पूंजी में अभिदान 4885.01.190.09.02.54 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)		प्रतिफल 2024-25		परिणाम 2024-25			
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (*)	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25	
	भारत सरकार	भारतीय निर्यात-आयात		उधार देने की बेहतर क्षमता	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	वर्ष 2023-24 की तुलना में	
0.01	द्वारा भारतीय	बैंक (एक्जिम) को			(एक्जिम) द्वारा ऋण देने में पिछले	वृद्धि	
0.01	निर्यात-आयात	इक्विटी पूंजी में निवेश	लागू नहीं (*)		वर्ष की तुलना में वृद्धि की		
	(एक्जिम) बैंक में	के रूप में दी गई राशि			प्रतिशतता		
	इक्विटी पूंजी	(करोड़ रुपए में)		अपेक्षित न्यूनतम विनियामकीय	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना	न्यूनतम विनियामकीय स्तर	
	निवेश			पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना	में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) का	के बराबर या उससे अधिक	
					%	पूंजी पर्याप्तता	
				संसाधन जुटाने की क्षमता (10 x	पिछले वर्ष की तुलना में जुटाए गए	वर्ष 2023-24 की तुलना में	
				एनओएफ)	संसाधनों में वृद्धि की प्रतिशतता	वृद्धि	

^(*) लागू नहीं क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वित्तीय परिव्यय नहीं है, केवल वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में आवंटित एक लाख रुपये की टोकन राशि है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के हिस्से का योगदान 5465.01.190.44.00.54 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय		प्रतिफल 2024-25		τ	गरिणाम 2024-2 5	
(करोड़ रुपए में)						
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (*)	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25
0(*)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों	पूंजी निवेश किए गए क्षेत्रीय	लागू नहीं (*)	विनियामकीय अपेक्षाओं को पूरा	9% के औसत	9% (सीआरएआर)
	(आरआरबी) में	ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)		करने के लिए जोखिम भारित	सीआरएआर तक पहुंचने	
	विनियामकीय पूंजी का	की संख्या		आस्तियों की तुलना में पूंजी	के लिए निवेश के बाद	
	निवेश			अनुपात (सीआरएआर) को	आरआरबी के पूंजी	
				बनाए रखना	पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि	

(*) लागू नहीं क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वित्तीय परिव्यय नहीं है|

व्यय वित्त सिमिति ने दिनांक 11.10.2021 को आयोजित अपनी बैठक में आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत भारत सरकार के हिस्से के रूप में 5,445 करोड़ रुपये के एकमुश्त अग्रिम पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 75% यानी 4,084 करोड़ रुपये आरआरबी में निवेश किए गए थे। वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के हिस्से के रूप में 1,361 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण समर्थन का शेष 25% व्यय विभाग की सहमित से राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) के पास रखा गया था। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में मांगे गए 1,361 करोड़ रुपये में से 1,100 करोड़ रुपये वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की प्रथम अनुपूरक मांगों में आवंटित किए गए थे। उक्त राशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरआरबी को जारी की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष 261 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान 4416.00.190.01.00.54 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	प्रतिफल 2024-25			परिणाम 2024-25		
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25(*)	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य २०२४-२५ (*)
0.01	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, नाबार्ड की 'उधार लेने की शक्ति' को 10 गुना तक बढ़ाना	नाबार्ड द्वारा सृजित विभिन्न निधियों में संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	लागू नहीं (*)	भारत सरकार के विभिन्न पहल विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए ऋण वृद्धि हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड को सहायता	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (भारत सरकार की विभिन्न निधियों/योजनाओं को लागू करने के लिए) जुटाए जाने को प्रस्तावित धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि

^(*) लागू नहीं क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वित्तीय परिव्यय नहीं है, केवल वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में आवंटित एक लाख रुपये की टोकन राशि है।

4. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए प्रचार-प्रसार / जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता 2235.60.110.07.00.31 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)		प्रतिफल 2024-25			परिणाम 2024-25	
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (*)	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (*)
0.01	पीएमजेजेबीवाई और	वित्तीय वर्ष के दौरान	लागू नहीं (*)	पीएमजेजेबीवाई और	मई 2024 में पॉलिसी वर्ष	मई 2024 में पॉलिसी वर्ष
	पीएमएसबीवाई के बारे में	जारी किए गए		पीएमएसबीवाई के	की समाप्ति के बाद दोनों	की समाप्ति के बाद दोनों
	जागरूकता फैलाने के लिए	विज्ञापनों की संख्या		तहत नामांकन बढ़ाने	योजनाओं के तहत	योजनाओं के तहत
	विज्ञापन अभियान			के लिए बढ़ी हुई	नामांकन में प्रतिशत वृद्धि	नामांकन में निम्नानुसार
				जागरूकता		प्रतिशत वृद्धि हैः
						पीएमजेजेबीवाई-5%
						पीएमएसबीवाई-10%

^(*) लागू नहीं क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वित्तीय परिव्यय नहीं है, केवल वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में आवंटित एक लाख रुपये की टोकन राशि है, तथापि, विज्ञापन के लिए राशि एलआईसी के पास उपलब्ध 21.40 करोड़ रुपए की मूल निधि में से जारी की जाएगी।

5. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) 2235.60.102.04.02.33 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय		प्रतिफल 2024-25			परिणाम 2024-25	
(करोड़ रुपए में)						
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25
422.78	एलआईसी को	जारी की गई राशि	422.78	प्रतिफल में कमी, यानी योजना के	योजना की अवधि के दौरान बेची गई	8.66 लाख मौजूदा
	सब्सिडी का भुगतान			प्रबंधन के लिए किए गए व्ययों के	पॉलिसियों को उनकी पॉलिसी अवधि	लाभार्थी
				अलावा एलआईसी द्वारा उत्पन्न	पूरी होने तक सेवित किया जाना	
				वास्तविक प्रतिफल और योजना के	आवश्यक है, इसलिए, इन पॉलिसियों के	
				तहत वरिष्ठ नागरिकों को सुनिश्चित	संबंध में सब्सिडी की प्रतिपूर्ति योजना के	
				प्रतिफल के बीच का अंतर भारत	नियमों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा	
				सरकार द्वारा ब्याज-अंतर सब्सिडी	निगम को की जाती है।	
				के रूप में वहन किया जाता है।		

^(*) पीएमवीवीवाई के तहत दिनांक 30.9.2023 तक लगभग 8.66 लाख मौजूदा लाभार्थियों को योजना की शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान की जाती रहेगी।

6. स्टैंड-अप इंडिया गारंटी निधि स्थापित करने के लिए एनसीजीटीसी को सहायता के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता 3465.01.190.08.03.31 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	प्रति	तेफल 2024-25		परिणाम 2024-25				
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25		
0.01	गारंटीकृत ऋण खातों	गारंटीकृत	पहली तिमाही –	स्टैंड अप इंडिया योजना	2024-25 में स्वीकृत किए गए ऋण	वार्षिक- 30000		
	की संख्या	ऋण खातों	63500	(एसयूपीआई) के तहत ग्रीनफील्ड	खातों की संख्या	पहली तिमाही – 5000		
		की संचयी		परियोजनाओं की स्थापना के लिए		दूसरी तिमाही – 9000		
		संख्या	दूसरी तिमाही –	अनुसूचित जाति / अनुसूचित		तीसरी तिमाही – 8000		
			65000	जनजाति और महिला उद्यमियों को		चौथी तिमाही – 8000		
				10 लाख रुपये से 100 लाख रुपये	महिलाओं को स्वीकृत किए गए	वार्षिक- 20000		
			तीसरी तिमाही –	के बीच ऋण की मंजूरी में वृद्धि	ऋण खातों की संख्या	पहली तिमाही – ४०००		
			67500			दूसरी तिमाही – 6000		
						तीसरी तिमाही – 5000		
			चौथी तिमाही –			चौथी तिमाही – 5000		
			70000		अनुसूचित जाति/अनुसूचित	वार्षिक- 10000		
					जनजाति के लाभार्थियों को स्वीकृत	पहली तिमाही – 1000		
					किए गए ऋण खातों की संख्या	दूसरी तिमाही – 3000		
						तीसरी तिमाही – 3000		
						चौथी तिमाही – 3000		

7. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 2235.60.102.05.02.31 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को वित्तीय सहायता और एपीवाई 2235.60.102.05.01.31 (सीएस) के अंतर्गत प्रचार अभियान के लिए पीएफआरडीए को वित्तीय सहायता

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)		प्रतिफल 2024-25	5		परिणाम 2024-25	
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (करोड़ रुपए में)	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25
245	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन राशि	एपीवाई सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि के लिए स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	पहली तिमाही - ₹155 करोड़ दूसरी तिमाही - ₹30 करोड़ तीसरी तिमाही - ₹30 करोड़ चौथी तिमाही – ₹30 करोड़	नामांकन और निरंतरता में वृद्धि हुई	एपीवाई के तहत नामांकित अभिदाताओं की संख्या	1.37 करोड़ (*)
5	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत प्रचार अभियान	प्रचार अभियानों के लिए स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	पहली तिमाही - ₹2.50 करोड़ दूसरी तिमाही - ₹1.50 करोड़ तीसरी तिमाही - 0 चौथी तिमाही – ₹1 करोड़	बेहतर जागरूकता से कवरेज, निरंतरता के स्तर में वृद्धि और अभिदाताओं को वृद्धावस्था सुरक्षा	एपीवाई के तहत नामांकित अभिदाताओं की संख्या	1.37 करोड़ (**)

^(*) इसका उद्देश्य एपीवाई योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के नामांकन और निरंतरता को बढ़ाना है। पूर्व प्रवृत्तियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.37 करोड़ का अनंतिम लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

^{(**) 1.37} करोड़ के अनंतिम नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रचार अभियान सहायता करेगा।

8. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इक्विटी को सहायता (सीएस) 4885.01.190.03.00.54 (आईएफसीआई)

वित्तीय परिव्यय		प्रतिफल 2024-25		परिणाम 2024-25			
(करोड़ रुपए में)							
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (*)	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25	
0.01	भारत सरकार द्वारा	भारतीय औद्योगिक वित्त	शून्य (*)	आस्ति देयता संतुलन को	ऋण कवरेज अनुपात में	कोई चूक न होना	
	भारतीय औद्योगिक वित्त	निगम (आईएफसीआई)		बनाए रखना	सुधार		
	निगम (आईएफसीआई)	में इक्विटी निवेश की राशि					
	में इक्विटी पूंजी निवेश	(करोड़ रुपए में		वित्तीय वर्ष के दौरान	कोई चूक नहीं	कोई चूक न होना	
				देयताओं का समय पर			
				पुनर्भुगतान			

^(*) लागू नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वित्तीय परिव्यय नहीं किया गया है, बजट अनुमान 2024-25 में केवल एक लाख रुपए की टोकन राशि आबंटित की गई।

9. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को सरकारी प्रतिभूति (बॉण्ड) 4885.01.190.19.00.54 (सीएस) के माध्यम से इक्विटी सहायता

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)		प्रतिफल 2024-25		परिणाम 2024-25		
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25
0	भारत सरकार द्वारा आईआईएफसीएल में इक्किटी पूंजी निवेश	आईआईएफसीएल में इक्किटी निवेश की राशि (करोड़ रुपए में)	लागू नहीं (*)	उधार देने की बेहतर क्षमता अपेक्षित न्यूनतम विनियामकीय पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना संसाधन जुटाने की क्षमता	(प्रतिशत में)	>0% ≥15% वर्ष 2023-24 की तुलना
				(10 x एनओएफ)	की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	में वृद्धि

^(*) लागू नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वित्तीय परिव्यय नहीं किया गया है।

10. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) को पूंजी सहायता 5465.01.190.52.00.54 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)		प्रतिफल 2024-25		परिणाम 2024-25			
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25	
0	भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) में इक्विटी पूंजी निवेश	्र और विकास बैंक (नैबफीड) को धनराशि इक्विटी पूंजी निवेश की		उधार देने की बेहतर क्षमता अपेक्षित न्यूनतम विनियामकीय पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना संसाधन जुटाने की क्षमता (10 x एनओएफ)	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक द्वारा ऋण देने में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (समतुल्य या अधिक) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (प्रतिशत में) (समतुल्य या अधिक) संसाधन जुटाने में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत	वृद्धि वर्ष 2023-24 की तुलना में	

^(*) लागू नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई वित्तीय परिव्यय नहीं है।

11. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत दिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को ऋण गारंटी निधि के लिए वित्तीय सहायता 3465.01.190.08.02.31 (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	प्रतिफल 2024-25			परिणाम 2023-24				
2024-25	प्रतिफल	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (लाख में)	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2024-25 (लाख करोड़ रुपए में)		
0.01	गारंटीकृत ऋण खातों की संख्या	गारंटीकृत ऋण खातों की कुल संख्या (लाख में)	पहली तिमाही – 150 दूसरी तिमाही – 152 तीसरी तिमाही – 154 चौथी तिमाही – 157	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋण (10 लाख रुपए तक के ऋण) में वृद्धि	इस योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा संवितरित की गई ऋण राशि और श्रेणी-वार उपलब्धि शिशु,	वार्षिक – 5.50 पहली तिमाही – 0.90 दूसरी तिमाही – 1.70 चौथी तिमाही – 1.80 शिशु – वार्षिक – 2.20 पहली तिमाही – 0.40 तीसरी तिमाही – 0.40 तीसरी तिमाही – 0.70 चौथी तिमाही – 0.70 पहली तिमाही – 0.30 दूसरी तिमाही – 0.40 तीसरी तिमाही – 0.60 चौथी तिमाही – 0.60 चौथी तिमाही – 0.20 दूसरी तिमाही – 0.20 दूसरी तिमाही – 0.30 तोसरी तिमाही – 0.30 तोसरी तिमाही – 0.40 चौथी तिमाही – 0.40 चौथी तिमाही – 0.40		

वित्त मंत्रालय लोक उद्यम विभाग वर्ष 2024-25 के लिए 500 करोड़ रूपए से कम के परिव्यय के साथ विभाग की सीएस/सीएसएस योजनाओ के लिए

आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)

	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना									
वित्तीय परिव्यय (रूपए करोड़ में)		आउटपुट 2024-25		आर	उटकम 2024-25					
2024-25	आउटपुट	सूचक	लक्ष्य	आउटकम	सूचक	लक्ष्य				
			2024-25			2024-25				
2.00	1. परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पृथक्कृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन			 परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पृथक्कृत कर्मचारियों के वीआरएस/ वीएसएस पुननिर्योजन के दायरे में वृद्धि 	वीएसएस विकल्पधारियों/ आश्रितों का	65%				

वित्त मंत्रालय सांग सं. 33 लोक उद्यम विभाग

वर्ष 2024-25 के लिए 500 करोड़ रुपये से कम के परिव्यय के साथ विभाग की सीएस / सीएसएस योजनाओं के लिए आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)

	अनुसंधान, विकास एवं परामर्श (आरडीसी)									
वित्तीय परिव्यय (रूपए करोड़ में)		आउटपुट 2024-25		आउटकम 2024-25						
2024-25	आउटपुट सूचक			आउटकम	सूचक	लक्ष्य				
			2024-25			2024-25				
6.38	सीपीएसईज़ तथा एसएलपीईज़ से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण/ सम्मेलन कार्यशालाएं आयोजित करना।	 1.1. सीपीएसईज़ तथा एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 1.2. सीपीएसईज़ के कार्यपालकों के लिए आयोजित कार्यशालाओं की संख्या 1.3. सीपीएसईज़ के निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए आयोजित ओरिएनटेशन कार्यक्रमों की संख्या 	15 6	एसएलपीईज़ के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान	 1.1. पूर्व वर्ष की तुलना में प्रशिक्षित कार्यपालकों की संख्या में % वृद्धि/कमी 1.2. पूर्व वर्ष की तुलना में आयोजित कार्यशालाओं की संख्या में % वृद्धि/कमी 1.3. पूर्व वर्ष की तुलना में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या में % वृद्धि/कमी 	10%				

INDEX

SI. No.	Departments	Page No.
1.	Demand No. 30- Department of Economics Affairs	17
i.	India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (CS)	17
2.	Demand No. 32-Department of Financials Services	18-28
i.	Subscription to Share Capital of Export Import Bank of India (EXIM) (CS)	18
ii.	Contribution of Government's share for recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs) (CS)	19
iii.	Subscription to share capital of NABARD (CS)	20
iv.	Funding support for publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) (CS)	21
V.	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) (CS)	22
vi.	Financial Support to National Credit Guarantee Trust Company (NCGTC) for Assistance to NCGTC to set up Stand-Up India Guarantee Fund (CS)	23
vii.	Funding support to PRDA for payment of incentive under Atal Pension Yojana (APY) and Funding Support to PFRDA for Promotional Campaign under APY (CS)	24
viii.	Equity support to Industrial Financial Corporation of India (IFCI) (CS)	25
ix.	Equity Support to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) through issuance of Govt. Securities Bond (CS)	26

X.	Capital Support to National Bank for Financing infrastructure and Development (NaBFID) (CS)	27
xi.	Financial Support to National Credit Guarantee Trust Company (NCGTC) for Credit Guarantee Trust Company (NCGTC) for Credit Guarantee fund for providing Guarantees to Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) (CS)	28
3.	Demand No.33 – Department of Public Enterprises	29-30
i.	Counselling, Retraining and Redeployment setting up of New Centres/addition of Nodal Agencies etc.	29

Department of Economic Affairs

India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) (CS)

FINANCIAL OUTLAY (₹ In Cr)		OUTPUTS 2024-25				OUTCOMES 2024-25			
2024-25	Output SI. Indicators Targets 2024-25				Outcome	SI. No.	Indicators	Targets 2024-25	
		1.1	No. of new projects received for support under IIPDF	15					
	No. of	1.2	No. of projects approved for funding.	12		2.1	No. of		
		1.3	No. of approved projects in which TA (Transaction Adviser) is appointed.	12	No. of projects bid out on the PPP model.				
25	projects received for support	1.4	No. of TA-appointed projects, in which Inception Report received.	10			projects in which the	6	
	under IIPDF	1.5	No. of TA-appointed projects, in which feasibility study received.	8			bids are floated.		
		1.6	No. of projects in which DPR (Detailed Project Report) and bid documents prepared by the TA.	6					
		1.7	Utilisation of IIPDF budget allocated.	100%					

Ministry of Finance Demand No.-32

Department of Financial Services

Output Outcome Monitoring Framework - FY 2024-25

1. Subscription to Share Capital of Export Import Bank of India (EXIM) 4885.01.190.09.02.54 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs. in cr)	OUTPUTS 2024-25		OUTCOMES 2024-25			
2024-25	Output	Indicators	Targets	Outcome	Indicators	Targets
			2024-25(*)			2024-25
	Equity capital	Amount provided		Improved lending capacity	Percentage increase in	Increase over
0.01	infusion in Exim	to Exim bank as	NA (*)		lending by Exim bank	2023-24
0.01	bank by	infusion to Equity			over last year	
	Government of	Capital (in Rs.		Maintain requisite	Percentage CRAR	Capital adequacy
	India	crore)		minimum regulatory	(Capital to Risk	at or above
				Capital Adequacy	(Weighted) Assets Ratio)	regulatory
						minimum
				Resource raising Capacity	Percentage increase in	Increase over
				(10 x NOF)	resources raised over	2023-24
					last Year	

^(*) Not applicable since no financial outlay in FY 2024-25, only token amount of Rs. one lakh allotted in BE 2024-25.

2. Contribution of Government's share for recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs) 5465.01.190.44.00.54 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)		OUTPUTS 2024-25		OUTCOMES 2024-25		
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25 (*)	Outcome	Indicators	Targets 2024-25
0(*)	Infusion of regulatory capital in RRBs	Number of RRBs infused with capital	NA (*)	Maintaining Capital to risk weighted assets ratio (CRAR) to meet regulatory requirements	Increase in RRBs capital adequacy ratio after infusion to reach average CRAR of 9%	9% (CRAR)

^(*) Not applicable since no financial outlay in FY 2024-25.

The Expenditure Finance Committee in its meeting held on 11.10.2021, approved a one-time upfront recapitalization of Rs.5,445 crore as Gol share under the scheme for Recapitalization of RRBs, 75% of which i.e.Rs.4,084 crore was infused into the RRBs during the FY 2021-22. The balance 25% of recapitalization support of Rs.1,361 crore as Gol share for the year 2022-23 was placed with National Investment Fund (NIF) as per the concurrence of D/o Expenditure. Out of Rs.1,361 crore demanded in RE 2023-24, Rs.1,100 crore was allocated in the First Supplementary Demands for Grants 2023-24. The said amount will be released during the current FY 2023-24 to the RRBs. The remaining amount of Rs.261 crore will be requested to allocate in FY 2024-25.

3. Subscription to share capital of NABARD 4416.00.190.01.00.54 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2024-25			OUTCOMES 2024-25		
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Targets 2024-25 (*)
			(*)			
0.01	Increase the	Amount disbursed	NA (*)	Assist NABARD to	Funds proposed to be	Increase over
	borrowing power	towards various		leverage credit increase	raised (for implementing	2023-24
	of NABARD to the	funds created by		for various GoI initiatives,	various GOI	
	extent of 10 times	NABARD (in Rs.		particularly benefitting the	funds/schemes) during	
	as per RBI	crore)		agriculture and allied	the year FY 2024-25 (in	
	guidelines			sectors	Rs. crore)	

^(*) Not applicable since no financial outlay in FY 2024-25, only token amount of Rs. one lakh allotted in BE 2024-25.

4. Funding support for publicity / awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) 2235.60.110.07.00.31 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)		OUTPUTS 2024-2	5		OUTCOMES 2024-2	25
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25 (*)	Outcome	Indicators	Targets 2024-25 (*)
0.01	Advertisement campaign to drive awareness for PMJJBY and PMSBY	Amount sanctioned for advertisements issued	NA (*)	Enhanced awareness to increase enrolments under PMJJBY and PMSBY	Percentage increase in the enrolment under both the schemes since the end of the policy year in May 2024	Percentage increase in the enrolment under both the schemes since the end of the policy year in May 2024 targeted: PMJJBY: 5% PMSBY: 10%

^(*) No financial outlay in FY 2024-25, only token amount of Rs. one lakh allotted in BE 2024-25, however, amount for advertisement will be released out of corpus of Rs.21.40 crore available with LIC.

5. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) 2235.60.102.04.02.33 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)		OUTPUTS 2024-25			OUTCOMES 2024-25	
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Targets 2024-25
422.78	Payment of Subsidy to LIC	Amount released	422.78	The differential return, i.e. the difference between actual return generated by LIC and the assured return to senior citizens under the scheme in addition to expenses incurred for managing the scheme are borne by Government of India as interest-gap subsidy.	their policy period, as such, subsidy in respect of these	8.66 lakhs existing beneficiaries

^(*) Around 8.66 lakhs existing beneficiaries as on 30.9.2023 under PMVVY will continue to be serviced according to the conditions of the scheme.

6. Financial Support to National Credit Guarantee Trust Company (NCGTC) for Assistance to NCGTC to set up Stand-Up India Guarantee Fund 3465.01.190.08.03.31 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2024-25			OUTCOMES 2024-25				
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Targets 2024-25		
0.01	Number of loan accounts guaranteed	Cumulative number of loan accounts to be	Q1 – 63500 Q2 – 65000	Increase in sanction of credit/ loan between Rs. 10 lakh to 100 lakh) to SC/ST and	Number of loan accounts sanctioned 2024-25	Yearly- 30000		
		guaranteed	Q3 – 67500	women entrepreneurs for setting up greenfield projects under Stand Up India Scheme		Q1 – 5000 Q2 – 9000 Q3 – 8000		
			Q4 – 70000	(SUPI)	Number of loan accounts sanctioned	Q4 – 8000 Yearly- 20000		
					to women	Q1 - 4000 Q2 - 6000 Q3 - 5000 Q4 - 5000		
					Number of loan accounts sanctioned to SCs/STs	Yearly- 10000		
					beneficiaries	Q1 – 1000 Q2 – 3000 Q3 – 3000 Q4 – 3000		

7. Funding support to PFRDA for payment of incentive under Atal Pension Yojana (APY) 2235.60.102.05.02.31 and Funding Support to PFRDA for Promotional Campaign under APY 2235.60.102.05.01.31 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	C	OUTPUTS 2024-25			OUTCOMES 2024-25	
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25 (Rs in Cr)	Outcome	Indicators	Targets 2024-25
245	Incentive to Atal Pension yojana (APY) Service providers (SPs)	Amount sanctioned for incentive to APY SPs (in Rs. Crore)	Q1-Rs.155 cr Q2- Rs.30 cr Q3- Rs.30 cr Q4 – Rs.30 cr	Increases enrolments and persistency	Number of subscribers enrolled under APY	1.37 crore(*)
5	Promotional Campaign under Atal Pension yojana (APY)	Amount sanctioned for Promotional campaigns (in Rs. Crore)	Q1-Rs.2.50 cr Q2- Rs.1.50 cr Q3- 0 Q4 – Rs.1 cr	Better awareness leading to more coverage, persistency levels, and Old age security to the subscribers	Number of subscribers enrolled under APY	1.37 crore(**)

^(*) Objective is to maximize subscriber enrolment and persistency in APY scheme. Based on past trends, a tentative target of 1.37 crore is fixed for FY 2024-25.

^(**) Tentative enrolment target of 1.37 crore is fixed. Promotional campaign will assist in achieving this target.

8. Equity support to Industrial Finance Corporation of India (IFCI) 4885.01.190.03.00.54 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2024-25			OUTCOMES 2024-25			
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Targets 2024-25	
			(*)				
0.01	Equity capital	Amount of equity	NA (*)	Maintaining Asset	Improvement in Debt	Occurrence of 'No	
	infusion in IFCI by	infusion provided		Liability balance	Coverage Ratio	Default Event'	
	Government of	to IFCI (in Rs.		Timely Repayment of	No Default	Occurrence of 'No	
	India	Crore)		Liabilities during the FY		Default Event'	

^(*) Not applicable since no financial outlay in FY 2024-25, only token amount of Rs. one lakh allotted in BE 2024-25.

9. Equity Support to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) through issuance of Govt. Securities (Bond) 4885.01.190.19.00.54 (CS)

Financial Outlay (Rs in Cr)		OUTPUTS 2024-25		Ol	JTCOMES 2024-25	
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Targets 2024-25
0	Equity capital infusion in IIFCL by Government	`	NA (*)	Improved lending capacity	Percentage increase in lending by IIFCL over last year	>0%
	of India	crore)		Maintain requisite minimum regulatory Capital Adequacy	Capital to Risk Assets Ratio (in percentage)	≥15%
				Resource raising Capacity (10 x NOF)	Percentage increase in resources raised over last Year	Increase over 2023-24

^(*) Not applicable since no financial outlay in FY 2024-25.

10. Capital Support to National Bank for Financing infrastructure and Development (NaBFID) 5465.01.190.52.00.54 (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	C	OUTPUTS 2024-25			OUTCOMES 2024-25	
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Targets 2024-25
0	Equity Capital infusion in National Bank for Financing Infrastructure and Development by	Amount provided to National Bank of Financing Infrastructure and Development as infusion to equity capital	NA (*)	Improved lending capacity	Percentage increase in lending by National Bank of Financing Infrastructure and Development over last year (greater than equal to)	Increase over 2023-24
	Government of India			Maintain requisite minimum regulatory Capital Adequacy Resource raising Capacity (10 x NOF)	Capital to Risk Assets Ratio (in percentage) (greater than equal to) Percentage increase in resources raised over last Year	Increase over 2023-24 Increase over 2023-24

^(*) Not applicable since no financial outlay in FY 2024-25.

11. Financial Support to National Credit Guarantee Trust Company (NCGTC) for Credit Guarantee Trust Company (NC

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUT	PUTS 2024-25			OUTCOMES 2023-24	
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25 (in lakhs)	Outcome	Indicators	Targets 2024- 25 (in Rs. lakh crore)
0.01	Number of loan accounts guaranteed	Cumulative number of loan accounts to be guaranteed (in Lakh)	Q1 – 150 Q2 – 152 Q3 – 154 Q4 – 157	Increase in collateral free credit (loans up to Rs. 10 lakh) under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	Amount of loan disbursed under the Scheme by Member Lending Institutions (MLIs) and category wise achievement Shishu,	Yearly - 5.50 Q1 - 0.90 Q2 - 1.10 Q3 - 1.70 Q4 - 1.80 Shishu - Yearly - 2.20 Q1 - 0.40 Q2 - 0.40 Q3 - 0.70 Q4 - 0.70 Kishore - Yearly - 2.00 Q1 - 0.30 Q2 - 0.40
					Tarun	Q3 - 0.60 Q4 - 0.70 Tarun - Yearly - 1.30 Q1 - 0.20 Q2 - 0.30 Q3 - 0.40 Q4 - 0.40

Ministry of Finance Demand No.-33

Department of Public Enterprises

Output-Outcome Framework (OOMF) 2024-25 for CS/CSS Schemes of the Department with outlay of less than Rs.500 crore.

	Counselling, Retraining and Redeployment (CRR) Scheme									
FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2024-25			C	OUTCOMES 2024-25					
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Target 2024-25				
2.00	Redeployment of separated employees through counselling and training.	1.1 Number of Voluntary Retirement Scheme (VRS)/ Voluntary Separation Scheme (VSS) optees /their dependents trained.	500	1.Increase the coverage of VRS/VSS redeployment of separated employees through counselling and training	1.1 % of VRS /VSS optees/ dependents redeployed	65%				

Ministry of Finance Demand No.-33

Department of Public Enterprises

Output-Outcome Framework (OOMF) 2024-25 for CS/CSS Schemes of the Department with outlay of less than Rs.500 crore.

		RESEARCH, DEVELOP	MENT AND C	ONSULTANCIES (I	RDC)	
FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2024-25				OUTCOMES 2024-25	
2024-25	Output	Indicators	Targets 2024-25	Outcome	Indicators	Target 2024-25
6.38	1. To undertake research studies, training, seminars, workshops on generic issues related to CPSEs and	 1.1 No. of Training programmes for executive of CPSEs and SLPEs conducted 1.2 No. of workshops for executives of CPSEs held 1.3 No. of orientation programmes for 		1. Coverage of research studies, training and workshops on generic issues to CPSEs and SLPEs	 1.1 % increase/ decrease in no. of trained executives over previous year 1.2 % increase/ decrease in no. of workshops organized over previous year 1.3 % of increase/ decrease in number of participated 	10%
	SLPEs	capacity building of Directors of CPSEs conducted	6		directors over previous year	10%